(b) The responsibility of the Central Government in respect of preservation is limited to monuments of national importance. Monuments other than those of national importance are looked after by the State Department of Archaeology and the Archaeological Survey of India renders technical assistance whenever asked for by the State Government.

वन-रोपण के बारे में स्वीडन के साथ समझौता

*175. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में 4 अक्तूबर, 1977 से लागू किये गये भारत और स्वीडन के बीच हुए वन-रोपण सबन्धी समझौतों की शर्तें क्या है,

(ख) इसमे कितनी राशि की भारतीय मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) इससे देश को कितना लाभ होने की सभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) दिनाक 4 अक्तूबर, 1977 को भारत सरकार और स्वीडन सरकार के बीच जो समझौता हुआ था, वह 'भारतीय काष्ठ-निष्कासन प्रशिक्षण परियोजना के लिए सहायता' के सबध मे था, न कि वन-रोपण के लिए तथापि, उपर्युक्त समझौता दिनाक 23 अप्रैल, 1977 का पत्रो के आदान-प्रदान के माध्यम से भारत सरकार और स्वीडन सरकार के बीच हुए मोटे समझौते का एक भाग था, जिसके अनुसार स्वीडन 1980-81 तक भारत मे वानिकी के विकास के लिए 200000 लाख स्वीडन क्रोनोर की सहायता प्रदान करेगा । "भारतीय काष्ठ-निष्कासन प्रशिक्षण परियोजना के लिए सहायता" सबधी परियोजना दिनांक 4-10-77 से साढे तीन वर्ष की अवधि के लिए है । इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

(1) मूल काष्ठ-निष्कासन कार्य मे लगभग 8,000–10,000 वन-कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना ।

(2) भारतीय वन अधिकारियो का यूरोपियन देशो मे उन्नत प्रौद्योगिकी मे प्रशिक्षण देना ।

(3) लकडी के सडक से परे और लम्बी दूरी के परिवहन मे सभावित सुधारो का पता लगाना ।

(4) एक अध्ययन, जिसका उद्देश्य आरा मिल तकनीको और देश, आरा मिल के उपकरणो के डिजाइन तथा विनिर्माण दोनो के सुधारो के सबध मे सुझाव देना है, के माध्यम से आरा मिल उद्योग के लिए सहायता देना ।

स्वेडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (स्वीडन-वन परामर्शदायी ए बी के माध्यम से) अधिक से अधिक 150 श्रम-महीनो तक विशेषज्ञो की सेवाए प्रदान करेगा, जिसमे एक परियोजना अधिकारी, मूल काष्ठ-निष्कासन के चार व्यावसायिक विशेषज्ञो, एक परिवहन विशेषज्ञ और एक आरा मिल विशेषज्ञ और उपर्युक्त विशेषज्ञता सबधी विषयो म अल्पावधि सलाहकार शामिल है । स्वेडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण परियाजनाओ के लिए 2,605,000 स्वीडन क्रोनोर के उपकरण भी प्रदान करेगा । स्वेडिश अतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण का ढाई वर्ष की अवधि के लिए कुल अंशदान 7,603,930 स्वीडन क्रोनोर होगा ।

(ख) परियोजना के लिए साढे तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार का अशदान 11,05,000 रुपये होगा, जिसमे मुख्य रूप से समकक्ष और सहायता सबधी कर्मचारी, लेखन-सामग्री और काष्ठ-निष्कासन प्रशिक्षण परियोजना के मुख्यालय देहरादून मे कार्यालय का स्थान शामिल है ।

(ग) इस परियोजना के क्रिया-वयन से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नलिखित है —

(1) आधुनिक औजारो और उनके उपयोग के आधुनिक तकनीको मे वन के कार्यकर्त्ताओ को परिचित कराके मूल काष्ठ-निष्कासन मे उनकी क्षमता बढाना । इसका तात्पर्य यह होगा कि उत्पादकता मे महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप वास्तविक रूप से भारत के काष्ठ-निष्कासन उद्यमो की अधिक वित्तीय लाभ होगा ।

(2) भारतीय वन अधिकारियो को मूल काष्ठ-निष्कासन, सडक से परे के वे परिवहन और लबी दूरी के परिवहन के सबध मे उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी प्रदान करना ।

उपर्युक्त दोनो लाभ आवश्यक समझे जाते है, क्योकि काष्ठ-निष्कासन सबधी कार्यों मे भारतीय वानिकी के कुल व्यय का लगभग 70 प्रतिशत व्यय होता है ।

जामिया मिलिया टिचर्स ट्रेनिंग कालेज, दिल्ली के विद्यार्थियो की मांगें

*176 श्री ओम प्रकाश त्यागी क्या शिक्षा, समाज कल्याण और सस्कृति मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) जामिया मिलिया टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, दिल्ली के विद्यार्थियो की अपनी हाल की हड़ताल के समर्थन मे क्या मांगे है ; और

(ख) सरकार ने अब तक इस संबध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसके शिक्षक प्रशिक्षण कालेज के छात्रों ने न तो हड़ताल की और न कोई मागे ही रखी ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

महाराष्ट्र में 'टाइगर प्रोजेक्ट' के लिए हवाई सर्वेक्षण

*177. श्री लक्ष्मण राव मानकर : क्या कृषि और सिंचाई मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या पूर्वी महाराष्ट्र की टाइगर प्रोजेक्ट योजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा नही किया गया था क्योकि सैंट्रल जलोजिकल सर्वे, हैदराबाद द्वारा उसका हवाई सर्वेक्षण नही किया गया था ;

(ख) क्या इस योजना का हवाई सवक्षण कार्य इस वर्ष पूरा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के आदिवासी क्षेत्र मे होने के कारण इसे प्राथमिकता प्रदान करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार के महा वनपाल द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के मेलघाट बाघ परियोजना क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नही किया गया है । इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान परियोजना क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नही है ।